

“विजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग/  
तक. 114-009/2003/20-01-03.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 51 ]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 19 दिसम्बर 2008—अग्रहायण 28, शक 1930

### विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम; (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 दिसम्बर 2008

क्रमांक ई-7/12/2008/1/2.—सुश्री ओमेगा यूनाईस टोप्पो, भा. प्र. से., उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग को दिनांक 08-12-2008 से 19-12-2008 तक (12 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 07, 20 एवं 21 दिसम्बर, 2008 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

- अवकाश से लौटने पर सुश्री टोप्पो, आगामी आदेश तक उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगी.
- अवकाश काल में सुश्री टोप्पो को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री टोप्पो अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

रायपुर, दिनांक 2 दिसम्बर 2008

क्रमांक ई-7/3/2007/1/2.—श्रीमती आर. शंगीता, भा. प्र. से., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बस्तर, जगदलपुर को दिनांक 21-01-2009 से 13-02-2009 तक (24 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 14 एवं 15 फरवरी, 2009 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है। साथ ही उन्हें उनके पति के व्यय पर विदेश पीट्सबर्ग (यू. एस. ए.) जाने की अनुमति भी दी जाती है।

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती आर. शंगीता, आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बस्तर, जगदलपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगी।
3. अवकाश काल में श्रीमती आर. शंगीता को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे।
4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती आर. शंगीता अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।
5. श्रीमती आर. शंगीता के उक्त अवकाश अवधि में श्री बी. पी. रात्रे, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बस्तर, जगदलपुर अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बस्तर, जगदलपुर का कार्य भी सम्पादित करेंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. के. बाजपेयी, उप-सचिव।

### राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 3 दिसम्बर 2008

क्रमांक/1913/प्र-1/अ. वि. अ./08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

| अनुसूची |       |                            |                                  | धारा 4 की उपधारा (2)<br>के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन<br>का वर्णन                |
|---------|-------|----------------------------|----------------------------------|--|--|
| जिला    | तहसील | भूमि का वर्णन<br>नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) |  |  |
| (1)     | (2)   | (3)                        | (4)                              | (5)  | (6)  |
| दुर्ग   | बालोद | भोयनापार<br>प. ह. नं. 7    | 0.31                             | कार्यपालन अभियंता, तान्दुला जल<br>संसाधन संभाग, दुर्ग। | परसाही माइनर अन्तर्गत<br>भूमि का अर्जन बाबत। |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बालोद के कार्यालय में देखा जा सकता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सुब्रत साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव।

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरिया, दिनांक 28 नवम्बर 2008

क्रमांक/12422/भू-अर्जन/08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन |           |           |   | धारा 4 की उपधारा (2)           | सार्वजनिक प्रयोजन  |
|---------------|-----------|-----------|---|--------------------------------|--|
| जिला          | तहसील     | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल<br>खसरा रकबा<br>नं. (हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन   |
| (1)           | (2)       | (3)       | (4)   | (5)                            | (6)  |
| कोरिया        | बैकुंठपुर | अमहर      | 35/3<br>0.05 हे.<br>(1800 वर्गफीट)                | कलेक्टर, कोरिया                | दीनदयाल ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत आवासहिनों के लिए भूमि अधिग्रहण. |

कोरिया, दिनांक 28 नवम्बर 2008

क्रमांक/12422/भू-अर्जन/08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन |           |           |   | धारा 4 की उपधारा (2)           | सार्वजनिक प्रयोजन  |
|---------------|-----------|-----------|---|--------------------------------|--|
| जिला          | तहसील     | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल<br>खसरा रकबा<br>नं. (हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन   |
| (1)           | (2)       | (3)       | (4)   | (5)                            | (6)  |
| कोरिया        | बैकुंठपुर | कोटकताल   | 265/1<br>1.51 हे.<br>में से 2700<br>वर्गफीट       | कलेक्टर, कोरिया                | दीनदयाल ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत आवासहिनों के लिए भूमि अधिग्रहण. |

कोरिया, दिनांक 28 नवम्बर 2008

क्रमांक/12422/भू-अर्जन/08.—चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन |            |           |                                    | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन  |
|---------------|------------|-----------|------------------------------------|----------------------|--|
| जिला          | तहसील      | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल                     | के द्वारा            | का वर्णन   |
|               |            |           | खसरा नं.                           | प्राधिकृत अधिकारी    |  |
| (1)           | (2)        | (3)       | (4)                                | (5)                  | (6)  |
| कोरिया        | बैकुण्ठपुर | खैरी      | 111                                | कलेक्टर, कोरिया      | दीनदयाल ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत आवासहिनों के लिए भूमि अधिग्रहण. |
|               |            |           | 1.73 हे.<br>में से 1800<br>वर्गफीट |                      |  |

कोरिया, दिनांक 28 नवम्बर 2008

क्रमांक/12424/भू-अर्जन/08.—चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन |       |           |                                    | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन  |
|---------------|-------|-----------|------------------------------------|----------------------|--|
| जिला          | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल                     | के द्वारा            | का वर्णन   |
|               |       |           | खसरा नं.                           | प्राधिकृत अधिकारी    |  |
| (1)           | (2)   | (3)       | (4)                                | (5)                  | (6)  |
| कोरिया        | सोनहत | सोनहत     | 89                                 | कलेक्टर, कोरिया      | दीनदयाल ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत आवासहिनों के भूमि अधिग्रहण. |
|               |       |           | 2.26 हे.<br>में से 2700<br>वर्गफीट |                      |  |

कोरिया, दिनांक 28 नवम्बर 2008

क्रमांक/12424/भू-अर्जन/08.—चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन |       |             |                |                                   | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन   |
|---------------|-------|-------------|----------------|-----------------------------------|----------------------|---|
| जिला          | तहसील | नगर/ग्राम   | लगभग क्षेत्रफल |                                   | के द्वारा            | का वर्णन  |
|               |       |             | खसरा           | रकबा                              | प्राधिकृत अधिकारी    |   |
| (1)           | (2)   | (3)         | नं.            | (हेक्टेयर में)                    | (5)                  | (6)   |
| कोरिया        | सोपहत | भुईहारीपारा | 37             | 6.00 हे.<br>में से 900<br>वर्गफीट | कलेक्टर, कोरिया      | दीनदयाल ग्रामीण आवास<br>योजना के अन्तर्गत<br>आवासहिनों के लिए<br>भूमि अधिग्रहण. |

कोरिया, दिनांक 28 नवम्बर 2008

क्रमांक/12424/भू-अर्जन/08.—चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन |       |           |                |                                    | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन   |
|---------------|-------|-----------|----------------|------------------------------------|----------------------|---|
| जिला          | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल |                                    | के द्वारा            | का वर्णन  |
|               |       |           | खसरा           | रकबा                               | प्राधिकृत अधिकारी    |   |
| (1)           | (2)   | (3)       | नं.            | (हेक्टेयर में)                     | (5)                  | (6)   |
| कोरिया        | सोनहत | बेलिया    | 297            | 1.90 हे.<br>में से 3600<br>वर्गफीट | कलेक्टर, कोरिया      | दीनदयाल ग्रामीण आवास<br>योजना के अन्तर्गत<br>आवासहिनों के लिए<br>भूमि अधिग्रहण. |

कोरिया, दिनांक 28 नवम्बर 2008

क्रमांक/12424/भू-अर्जन/08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन |       |           |   | धारा 4 की उपधारा (2)           | सार्वजनिक प्रयोजन  |
|---------------|-------|-----------|---|--------------------------------|--|
| जिला          | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल<br>खसरा रकबा<br>नं. (हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन   |
| (1)           | (2)   | (3)       | (4)   | (5)                            | (6)  |
| कोरिया        | सोनहत | करी       | 12/2<br>4.82 हे.<br>में से 900<br>वर्गफीट         | कलेक्टर, कोरिया                | दीनदयाल ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत आवासहिनों के लिए भूमि अधिग्रहण. |

कोरिया, दिनांक 28 नवम्बर 2008

क्रमांक/12424/भू-अर्जन/08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन |       |           |                                 | धारा 4 की उपधारा (2)           | सार्वजनिक प्रयोजन  |
|---------------|-------|-----------|---------------------------------|--------------------------------|--|
| जिला          | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल<br>(वर्गफीट में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन   |
| (1)           | (2)   | (3)       | (4)                             | (5)                            | (6)  |
| कोरिया        | सोनहत | काचरडांड  | 1800<br>वर्गफीट                 | कलेक्टर, कोरिया                | दीनदयाल ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत आवासहिनों के लिए भूमि अधिग्रहण. |

कोरिया, दिनांक 28 नवम्बर 2008

क्रमांक/12424/भू-अर्जन/08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन |       |           |                |                     | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन  |
|---------------|-------|-----------|----------------|---------------------|----------------------|--|
| जिला          | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल |                     | के द्वारा            | का वर्णन   |
|               |       |           | खसरा           | रकबा                | प्राधिकृत अधिकारी    |  |
|               |       |           | नं.            | (हेक्टेयर में)      |                      |  |
| (1)           | (2)   | (3)       | (4)            |                     | (5)                  | (6)  |
| कोरिया        | सोनहत | महुआपारा  | 177            | 4.73                | कलेक्टर, कोरिया      | दीनदयाल ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत आवासहिनों के लिए भूमि अधिग्रहण. |
|               |       |           |                | में से 1800 वर्गफीट |                      |  |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
कमलप्रीत सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं  
पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

खसरा नम्बर  
(1)  
रकबा  
(एकड़ में)  
(2)

दुर्ग, दिनांक 6 दिसम्बर 2008

क्रमांक/2611/16 अ/82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला-दुर्ग

(ख) तहसील-डौण्डीलोहारा

(ग) नगर/ग्राम-कोटेरा, प. ह. नं. 26

(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.28 एकड़

|           |      |
|-----------|------|
| 2262      | 0.15 |
| 2251      | 0.13 |
| 2444      | 0.21 |
| 2253      | 0.28 |
| 2457      | 0.10 |
| 2388/1    | 0.08 |
| 2397      | 0.12 |
| 2433      | 0.13 |
| 2449      | 0.18 |
| 2448/2974 | 0.03 |
| 2387      | 0.36 |
| 2259      | 0.08 |
| 2247/1    | 0.42 |
| 2454      | 0.08 |
| 2440      | 0.03 |
| 2441      | 0.08 |
| 2446      | 0.08 |

| (1)       | (2)     |
|-----------|---------|
| 2396/1    | 0.11    |
| 2455      | 0.09    |
| 2388/2    | 0.15    |
| 2458      | 0.08    |
| 2432      | 0.08    |
| 2438/1    | 0.05    |
| 2438/4    | 0.30    |
| 2448      | 0.13    |
| 2394/1    | 0.09    |
| 2246      | 0.04    |
| 2399      | 0.07    |
| 2427/1    | 0.03    |
| 2426      | 0.31    |
| 2260      | 0.48    |
| 2252      | 0.16    |
| 2263      | 0.16    |
| 2431      | 0.03    |
| 2452      | 0.20    |
| 2453      | 0.12    |
| 2441/2973 | 0.03    |
| 2395      | 0.24    |
| 2438/2    | 0.16    |
| 2247/2    | 0.28    |
| 2393      | 0.22    |
| 2442      | 0.15    |
| 2443      | 0.16    |
| 2447      | 0.01    |
| 2396/2    | 0.15    |
| 2456      | 0.10    |
| 2398      | 0.08    |
| 2430      | 0.05    |
| 2451      | 0.02    |
| 2438/3    | 0.13    |
| 2438/5    | 0.13    |
| 2439      | 0.02    |
| 2394/2    | 0.08    |
| 2437      | 0.05    |
| योग       | 54 7.28 |

(2). सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सुब्रत साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं  
पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,  
राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 16 दिसम्बर 2008

क्रमांक/अविअ/भू-अर्जन/प्र. क्र. 04/अ-82/वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-आरंग
- (ग) नगर/ग्राम-राखी, प. ह. नं. 71/16
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-10.14 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा<br>(हेक्टेयर में) |
|------------|------------------------|
| (1)        | (2)                    |
| 231        | 7.60                   |
| 481        | 0.82                   |
| 592        | 0.60                   |
| 725        | 1.00                   |
| 856        | 0.123                  |
| योग        | 5 10.14                |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-नई राजधानी योजनान्तर्गत कैंपीटल कॉम्पलेक्स हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी आरंग/अभनपुर मुख्यालय, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
विकास शील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.